झारखंड उच्च न्यायालय रांची

एलपीए सं **448/2023** के साथ

अंतर्वर्ती आवेदन सं 7710/**2023**

सैयद जाकिर हुसैन, पिता- स्वर्गीय सैयद मोहम्मद अनवर पंडित, आयु- लगभग 52 वर्ष, चास, डाकघर एवं थाना- चास, जिला- बोकारो

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. सचिव, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुरवा, डाकघर एवं थाना- धुरवा, जिला- रांची
3. उपायुक्त, बोकारो, डाकघर एवं थाना- बोकारो, जिला- बोकारो

विरोधी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता के लिए:श्रीमती रिंकू भक्त, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री मोहम्मद असगर, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता II के सहायक अधिवक्ता

05/ दिनांक : 29.01.2024

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के अनुसारः

1. लेटर पेटेंट के खंड 10 के तहत तत्काल अंतर-अदालत अपील, डब्ल्यू. पी. में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका(एस) सं. 4918/2017 मामले में पारित दिनांकित 13.12.2022 आदेश/निर्णय जिसके द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई है, के खिलाफ निर्देशित की जाती है।

<u>अंतर्वर्ती आवेदन सं **7710/2023**</u>

2. तत्काल अपील को सीमा द्वारा वर्जित माना जाता है क्योंकि अपील को प्राथमिकता देने में 219 दिनों की देरी हुई है, इसलिए इस तरह की देरी को माफ करने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 7710/2023होने के कारण एक आवेदन दायर किया गया है।

3. यह न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल अंतर-न्यायालय अपील 219 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई है, यह उचित और सही समझता है कि योग्यता के आधार पर विवादित आदेश की वैधता और औचित्य में जाने से पहले विलंब माफी आवेदन पर विचार किया जाए।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपील को प्राथमिकता देने में देरी को तत्काल मध्यस्थ आवेदन को उसमें दिखाए गए आधारों के आधार पर अनुमति देकर माफ किया जा सकता है जो इसे पर्याप्त मानते हैं।

5. अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करने का आधार, जैसा कि अंतर्वर्ती आवेदन में उल्लेख किया गया है, यह है कि अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता को मामले के निपटारे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उसने मामले की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की है, तो यह उसके संज्ञान में आया है कि उसका मामला पहले ही 13.12.2022 पर खारिज कर दिया गया है।

6. इसके तुरंत बाद, 27.07.2023 को, अपीलार्थी ने दिनांकित 13.12.2022 आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया है और रिट याचिका (एस)संख्या.4918/2017में रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता को मामले को खारिज करने के बारे में सूचित नहीं किया है, जिसके कारण तत्काल अपील करने में 219 दिनों की देरी हुई है।

7. हमने विलंब माफी आवेदन पर अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुना है और उस पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय कुछ कानूनी प्रस्ताव को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यधिक देरी को माफ करने में न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में प्रस्तावित किया गया है।

8. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि आम तौर पर दायर किये गए वाद. को सीमा के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से यदि अपील दायर करने में अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह दायर किये गए वाद की योग्यता में प्रवेश करने से पहले देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करे।

9. इसमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सीमा कानून का कानूनी निहितार्थ है कि यह सामान्य कल्याण के लिए है कि एक अवधि मुकदमेबाजी के लिए रखी जाए। सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं,बल्कि विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निर्धारित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए, जैसा कि बृजेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,(2014) 11 एस. सी. सी. 351 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया है।

10. प्रिवी काउंसिल ने जनरल एक्सीडेंट फायर एंड लाइफ एस्योरेंस कॉर्प लिमिटेड बनाम जनमहम्मद अब्दुल रहीम(1939-40) 67अंतर्वर्ती आवेदन 416, टैगोर लॉ लेक्चरर्स, 1932 मामले में श्री मित्रा के लेखन पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है किः

> "सीमा और प्रिस्क्रिप्शन का कानून किसी विशेष मामले में कठोर और अन्यायपूर्ण रूप से काम करता प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि कानून एक सीमा का प्रावधान करता है, तो इसे किसी विशेष पक्ष के लिए कठिनाई के जोखिम पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश, न्यायसंगत आधारों पर, कानून द्वारा अनुमत समय को बढ़ा नहीं सकता है, इसके संचालन को स्थगित नहीं कर सकता है, या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अपवादों को पेश नहीं कर सकता है।"

11. पी. के. रामचंद्रन बनाम केरल राज्य, (1997) 7 एस. सी. सी. 556 मामले में, शीर्ष न्यायालय ने 565 दिनों की देरी की माफी के मामले पर विचार करते हुए, जिसमें देरी की माफी के लिए उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण से कम कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, पैराग्राफ-6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "6. सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है लेकिन इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू करना पड़ता है जब क़ानून इस तरह निर्धारित करता है और अदालतों के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं होती है।“

12. इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, यह न्यायालय ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी, (2013) 12 एस. सी. सी. 649मामले में, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

“21. 5 (v) विलंब को क्षमा करने की मांग करने वाले पक्ष के लिए ईमानदारी की कमी एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

21. 7 (vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित करना होगा और इसे पूरी तरह से निर्बाध स्वतंत्र खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21. 9. (ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

22. 4. (घ) विलम्ब को एक गैर-गंभीर विषय के रूप में समझने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को बेपरवाह तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मानकों के भीतर, इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।“

13. कानून की यह स्थिर स्थिति है कि जब कोई वादी नेक इरादे से कार्य नहीं करता है और साथ ही, अपनी ओर से निष्क्रियता और लापरवाही के कारण, अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसे नेक इरादे की कमी और घोर निष्क्रियता और लापरवाही महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें देरी की माफी के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

14. रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, (1962) 2 एस. सी. आर. 762 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि दिए गए मामले के तथ्यों में पर्याप्त कारण बनाया गया है, अपीलार्थी को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। पैराग्राफ-12 में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः –

"12. हालाँकि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी एक पक्ष अधिकार के रूप में प्रश्न में देरी की माफी का हकदार नहीं है। धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन अधिकारिता के प्रयोग के लिए पर्याप्त कारण का प्रमाण एक पूर्ववर्ती शर्त है।यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो आगे कुछ नहीं किया जाना चाहिए; देरी को माफ करने के लिए आवेदन को केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो अदालत को यह पूछना होगा कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए।इस मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पक्ष की परिश्रम या उसकी ईमानदारी पर विचार

किया जा सकता है; लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होगा जिन्हें अदालत प्रासंगिक मान सकती है।यह इस जांच को उचित नहीं ठहरा सकता कि पार्टी अपने पास उपलब्ध सभी समय के दौरान बेकार क्यों बैठी रही। इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि जब न्यायालय सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए आवेदनों पर विचार कर रहा होता है तो ईमानदारी या उचित परिश्रम के विचार हमेशा सामग्री और प्रासंगिक होते हैं। ऐसे आवेदनों से निपटने में न्यायालय से धारा 5 और 14 के संयुक्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा जाता है। इसलिए, हमारी राय में, धारा 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सामग्री और प्रासंगिक बनाए गए विचारों को उन आवेदनों से निपटने में उसी हद तक और उसी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है जो केवल धारा 14 के तहत, बिना धारा 5 के संदर्भ के, तय किए जाते हैं। वर्तमान मामले में यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि विवेकाधिकार का उपयोग अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना चाहिए क्योंकि सीमा की अवधि के दौरान अपीलार्थी की परिश्रम की कमी के खिलाफ की गई सामान्य आलोचना के अलावा इसके खिलाफ कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।वास्तव में, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, विद्वत न्यायिक आयुक्त ने विलंब की माफी के लिए अपीलार्थी के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर जल्द से जल्द अपील दायर करना अपीलार्थी का कर्तव्य था, और यह, हमारी राय में, एक वैध आधार नहीं है।

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विलम्ब क्षमा आवेदन पर विचार करते समय, विधि न्यायालय को विलम्ब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण के साथ-साथ वादी के दृष्टिकोण पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या यह प्रामाणिक है या नहीं, क्योंकि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक अधिकार अर्जित किया जाता है और इस प्रकार, वादी के प्रामाणिक उद्देश्य पर ध्यान देना आवश्यक है और साथ ही, उसकी ओर से निष्क्रियता और अड़चनों के कारण भी।

16.इसमें यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि 'पर्याप्त कारण' का अर्थ क्या है। बसावराज और अन्यबनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, [(2013) 14 एस. सी. सी. 81]मामले में 'पर्याप्त कारण' के अर्थ पर विचार किया गया है।, जिसमें यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 9 से 15 में अभिनिर्धारित किया गया हैः –

"9. पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "पर्याप्त" या "पर्याप्त" है, क्योंकि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है।इसलिए, "पर्याप्त" शब्द में उससे अधिक कुछ नहीं है जो

एक तर्क प्रदान करता है, जो जब कार्य किया जाता है तो किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, जिसकी विधिवत जांच एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से की जाती है।इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "लगन से काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"।हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए ताकि संबंधित अदालत इस कारण से विवेक का प्रयोग कर सके कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक तरीकाथा।(देखें मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336], माता दिन बनाम ए. नारायणन [(1969) 2 एस. सी. सी. 770: ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1953], परिमल बनाम वीणा [(2011) 3 एस. सी. सी. 545: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1: ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1150] और मनीबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम। बृहन्मुंबई का [(2012) 5 एस. सी. सी. 157: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 24: ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1629]।)

10. अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993] में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच के अंतर को समझाया और कहा कि प्रत्येक "पर्याप्त कारण" एक अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालाँकि, यदि कोई अंतर मौजूद है तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का पालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाए।

11. "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई सीधासटीकसूत्र संभव नहीं है।(मदनलाल बनाम श्यामलाल [(2002) 1 एस. सी. सी. 535:

ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 100] और राम नाथ साओ बनाम गोवर्धन साओ [(2002) 3 एस. सी. सी. 195: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1201]के अनुसार।)

12. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून इस तरह से निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।"एक वैधानिक प्रावधान से निकलने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है। एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए मानता है।" वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूरी तरह से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।कानूनी उक्ति "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है। यह लगातार माना गया है कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

13.सीमा का क़ानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है, इसका उद्देश्य समुदाय में शांति सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है। यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो अस्पष्ट रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं और समय के साथ बासी हो गए हैं। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के अनुसार, वॉल्यूम 28, पृ. 266:

"605. सीमा अधिनियमों की नीति-न्यायालयों ने सीमाओं के कानूनों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात् (1) लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) हो सकता है कि एक प्रतिवादी ने किसी पुराने दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिए हों, और (3) कार्रवाई के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।"

एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, सीमा लंबे समय तक आनंद लेने से समानता और न्याय में जो हासिल किया जा सकता है या जो किसी पक्ष की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या बाधाओं से खो गया हो सकता है, उसमें गड़बड़ी या अभाव को रोकती है।(पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम एस. बी. आई. कर्मचारी संगठन देखें। [(2005) 7 एस. सी. सी. 510], राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह [(1973) 2 एस. सी. सी.

705: ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2537] और पुंडलिक जलम पाटिल बनाम जलगांव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एस. सी. सी. 448]

14. पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य [(2002) 4 एस. सी. सी. 578] मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को शामिल करना कानून बनाने के बराबर है और यह अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक [(1992) 1 एस. सी. सी. 225] मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत होगा।

15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जो उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है।यदि कोई पक्ष लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से ईमानदारी का अभाव पाया जाता है, या परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है। किसी भी अदालत को किसी भी शर्त को लागू करके इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।आवेदन पर निर्णय केवल विलंब की माफी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाना है। यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका की घोर अवहेलना करने के समान है।"

17. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"।हालाँकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को इस कारण से संबंधित न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए कि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण थी जैसा किमनिंद्र

लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। भूतनाथ बनर्जी और अन्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336, लाला मातादीन बनाम ए. नारायणन, (1969) 2 एस. सी. सी. 770, परिमल बनाम। वीणा @भारती, (2011) 3 एस. सी. सी. 545 और मनीबेन देवराज शाह वर्सेज। बृहन्मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157मामलेमें कहा गया है।

18. उपरोक्त निर्णयों में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई सीधासटीक सूत्र संभव नहीं है।इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम नाथ साव उर्फराम नाथ साहू और अन्य बनाम गोवर्धन साओ और अन्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 195मामलों में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है;जिसमेंपैराग्राफ-12 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः –

> "12. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 5 या संहिता के आदेश 22 नियम 9 या किसी अन्य समान प्रावधान के अर्थ के भीतर "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी किसी पक्ष के लिए आरोप योग्य न हो।किसी विशेष मामले में प्रस्तुत स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" का गठन करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कदम उठाने में हुई देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई सीधासटीक सूत्र नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अदालतों को दिखाए गए कारण में गलती खोजने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निपटान अभियान के अति-समन्वय में एक गलत आदेश द्वारा याचिका को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार होना चाहिए, एक अपवाद, विशेष रूप से तब जब चूक करने वाले पक्ष पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, मामले पर विचार करते समय अदालतों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाने से दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ है जिसे नियमित रूप से देरी को माफ करके हल्के में पराजित नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, मामले के बारे में एक पांडित्यपूर्ण और अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से दिए गए स्पष्टीकरण को तब खारिज नहीं किया जाना चाहिए जब मामले में दांव अधिक हों और/या तथ्यों और कानून के तर्कपूर्ण बिंदु शामिल हों, जिससे उस पक्ष को भारी

नुकसान और अपूरणीय क्षति हो, जिसके खिलाफ वादया तो डिफ़ॉल्ट रूप से या निष्क्रियता से समाप्त हो जाता है और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए ऐसे पक्ष के मूल्यवान अधिकार को विफल कर देता है।मामले पर विचार करते समय, अदालतों को उस आदेश के परिणामी प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा जो यह दोनों पक्षों को किसी भी तरह से पारित करने जा रहा है।“

19. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है, जिसमें 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति से निपटा गया है, जिसका अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"।

20. यह न्यायालय, उपरोक्त प्रस्ताव और 219 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए विलंब माफी आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या प्रस्तुत स्पष्टीकरण को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण कहा जा सकता है।

21. जैसा कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है, जिसमें यह कहा गया है कि अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता को मामले के निपटारे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उसने मामले की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की है, तो यह उसके संज्ञान में आया है कि उसका मामला पहले ही 13.12.2022 पर खारिज कर दिया गया है।

22. इसके तुरंत बाद, 27.07.2023 को अपीलार्थी ने दिनांकित 13.12.2022 आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया है। चूंकि 2017 की रिट याचिका(एस) संख्या 4918 में रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता को मामले को खारिज करने के बारे में सूचित नहीं किया है और इसलिए तत्काल अपील करने में 219 दिनों की देरी हुई है।

23. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि विलंब माफी आवेदन में अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, अत्यधिक देरी के कारण को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विवादित निर्णय 13.12.2022 पर पारित किया गया था और विवादित निर्णय की प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध 27.07.2023 पर किया गया था।लेकिन उक्त अंतर्वर्ती आवेदन में उस प्रभाव का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि केवल यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को मामले के निपटारे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उसने मामले की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की है, तो यह उसके संज्ञान में आ गया है कि उसका मामला पहले ही 13.12.2022 पर खारिज कर दिया गया है, इस

प्रकार, यह अपीलार्थी के अपने निर्णय के प्रति कठोर दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसे 219 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है।

24. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने एल.पी.ए. संख्या. 86/2021में विलंब माफी आवेदन को खारिज करने पर एक आदेश पारित किया है क्योंकि देरी को माफ करने के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के लगभग 687 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की गई थी।

25. एल.पी.ए. संख्या.835/2019में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश में एक अन्य मामले का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जिसमें 568 दिनों की देरी को माफ करने का मुद्दा विचाराधीन था।

26. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने राज्य अपीलार्थियों द्वारा उसमें प्रस्तुत कारण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके फाइल को एक मेज से दूसरी मेज पर ले जाने के आधार पर पर्याप्त कारण नहीं पाया है, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

27. राज्य अपीलार्थी ने एस.एल.पी. संख्या 7755/2022के रूप में एस. एल. पी. दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा की है और एल.पी.ए. संख्या 835/2019 में पारित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन उक्त एस.एल.पी. संख्या 7755/2022 को खारिज कर दिया गया है जैसा कि दिनांकित 13.05.2022 के आदेश से प्रतीत होता है।

28. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल, 2023 को झारखंड राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति (सी) संख्या 8378-379/2023 को भी खारिज कर दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा एल. पी.ए. संख्या 99/2021 में पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपील दायर करने में 534 दिनों की देरी के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया था।

29. इस न्यायालय का विचार है कि ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात और विलंब माफी आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, अपील दायर करने में 219 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है।

30. तदनुसार, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 7710/2023विलंब माफी आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

31. इसके परिणामस्वरूप, यह अपील भी खारिज हो जाती है।

32. अपील खारिज होने के परिणामस्वरूप, लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हों, भी खारिज कर दिए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|